

MAIN NEWS HEADLINE जब पुल सिवाले से आधार कार्ड बनवाने के मांगे 100 रु

वषिय सूची (Table of Contents):

- >> 1. दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा 100 रुपये में फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाने वाले...
- >> सस्ते दाम में असली जैसी नकली पहचान...
- >> 2. सोशल मीडिया और साइबर पेट्रोलिंग से कैसे मिला फर्जी वेबसाइट का सुराग?...
- >> bkprint.in वेबसाइट के दावों ने चौंकाया...
- >> 3. पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन डमी अकाउंट और 100 रुपये देकर खुद बनवाया फर्जी दस्ता...
- >> डमी यूजर बनकर जाल में फंसाया...
- >> 4. बिल्कुल असली दखिने वाले दस्तावेजों का सच QR कोड की जांच से खुला वेबसाइट का र...
- >> फर्जी QR Code का तकनीकी विश्लेषण...
- >> 5. पहचान की चोरी से लेकर बैंक फ्रॉड तक इन फर्जी दस्तावेजों के खतरनाक मंसूबे...
- >> साइबर अपराधों में होने वाला दुरुपयोग...
- >> 6. दमन से बदिशी साव और पटना से संतोष कुमार गरिफ्तार ऐसे हुआ आरोपियों तक पुलिस ...
- >> दमन और पटना में बैंक-टू-बैंक छापेमारी...
- >> जब्त किए गए डिजिटल उपकरण...
- >> 7. वॉलेट रचार्ज से लेकर फर्जी आईडी प्रिंट होने तक जानिए कैसे काम करती थी यह अव...
- >> अवैध बिजनेस मॉडल के मुख्य चरण...
- >> 8. दिल्ली पुलिस की आम जनता से अपील सरकारी दस्तावेजों के लिए सरिफ आधिकारिक पोर्...
- >> सुरक्षित रहने के लिए इन बातों का रखें ध्यान...
- >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न...

प्रस्तावना (Introduction): डिजिटल युग में जहां हर काम ऑनलाइन चुटकियों में हो जाता है, वहीं साइबर अपराधी भी मासूम नागरिकों को ठगने के नए-नए पैतरे अपना रहे हैं। आज के समय में आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर कुछ ऐसी फर्जी वेबसाइटें भी सक्रिय हैं जो महज कुछ ही मिनटों में हुबहु असली दखिने वाले सरकारी दस्तावेज बनाने का दावा करती हैं? हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ही अंतर-राज्यीय (Inter-State) साइबर गरीह का पर्दाफाश किया है जो मात्र 100 रुपये लेकर नकली आईडी कार्ड्स का अवैध कारोबार चला रहा था। आइए इस पूरे मामले को वस्तुतः समझते हैं ताकि आप भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकें।

1. दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा: 100 रुपये में फर्जी आधार और

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अंतर्गत आने वाली Intelligence Fusion and Strategic Operations (IFSO) यूनिट ने एक

बहुत बड़े साइबर रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह गरीह देश के अलग-अलग राज्यों में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से नकली सरकारी दस्तावेज (Fake Government Documents) तैयार करने का अवैध धंधा चला रहा था।

सस्ते दाम में असली जैसी नकली पहचान

शुरुआती जांच और लेटेस्ट अपडेट (latest update) के अनुसार, यह गरीह मात्र 100 रुपये जैसी मामूली रकम लेकर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, नविस प्रमाण पत्र, जातिप्रमाण पत्र और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाकर बेच रहा था। पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो देश के अलग-अलग कोनों से इस संगठित अपराध को अंजाम दे रहे थे।

2. सोशल मीडिया और साइबर पेट्रोलिंग से कैसे मिला फर्जी वेबसाइट

इस बड़े रैकेट का खुलासा दिल्ली पुलिस की मुस्तैद साइबर पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कारण संभव हो पाया है। इंटरनेट पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते समय पुलिस टीम को एक विशेष वेबसाइट के बारे में इनपुट मिला।

bkprint.in वेबसाइट के दावों ने चौकाया

जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने देखा कि bkprint.in नाम की एक वेबसाइट सरेआम यह दावा कर रही थी कि उनके पोर्टल पर आकर कोई भी व्यक्ति कुछ ही मिनटों में अपना आधार, पैन या वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकता है। सरकारी प्रक्रियाओं में समय लगने के बावजूद यह साइट तुरंत दस्तावेज देने की गारंटी दे रही थी, जिसने साइबर सेल के अधिकारियों के कान खड़े कर दिए।

>> वेबसाइट पर सभी प्रमुख सरकारी प्रमाण पत्रों के फॉर्म उपलब्ध थे।

>> यूजर से बेहद कम शुल्क लेकर डेटा कलेक्ट किया जा रहा था।

>> सर्च इंजन पर खुद को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कई भ्रामक कड़ियों का सहारा लिया था।

3. पुलिस का स्टगि ऑपरेशन : डमी अकाउंट और 100 रुपये देकर खु

वेबसाइट की सच्चाई को परखने और पुख्ता सबूत जुटाने के लिए IFSO यूनिट के जांच अधिकारियों ने एक अनोखा स्टगि ऑपरेशन प्लान किया। उन्होंने सीधे छापेमारी करने के बजाय एक आम ग्राहक बनकर वेबसाइट की कार्यप्रणाली की जांच करने का फैसला किया।

डमी यूजर बनकर जाल में फंसाया

पुलिस अधिकारी ने वेबसाइट पर जाकर एक डमी अकाउंट (Fake Account) बनाया। इसके बाद, वेबसाइट के नयिमों के अनुसार पोर्टल से जुड़े यूपीआई (UPI) अकाउंट के माध्यम से उनके डिजिटल वॉलेट में 100 रुपये ट्रांसफर किए गए। वॉलेट रचिरज होते ही पुलिस ने एक काल्पनिक नाम, फर्जी पता और एक रैंडम फोटो अपलोड कर दी और आधार कार्ड व वोटर आईडी के लिए अप्लाई (apply online) कर दिया।

कुछ ही मिनटों के भीतर वेबसाइट ने एक चमचमाता हुआ डिजिटल कार्ड जनरेट कर दिया, जो देखने में हूबहू असली सरकारी पहचान पत्र जैसा था। इस लाइव टेस्टिंग ने साबित कर दिया कि यह पूरी वेबसाइट एक बड़ा फ्रॉड है। अगर आप अपने असली कार्ड में सुधार करना चाहते हैं, तो हमेशा वैध तरीकों का ही पालन करें जैसे आप आधार कार्ड अपडेट हुआ आसान! नई दस्तावेज़ लसिट से अब नाम, पता और DOB बदलें झटपटलेख के माध्यम से सही प्रक्रिया जान सकते हैं।

4. बलिकूल असली देखने वाले दस्तावेजों का सच: QR कोड की जांच

जब पुलिस टीम ने वेबसाइट द्वारा तैयार किए गए फर्जी आधार और वोटर आईडी को बारीकी से देखा, तो वे हैरान रह गए। पहली नजर में कोई भी आम नागरिक या सुरक्षाकर्मी यह नहीं बता सकता था कि यह दस्तावेज नकली है। कार्ड का फॉन्ट, रंग और लेआउट पूरी तरह से आधिकारिक यूआईआईआई (UIDAI) या चुनाव आयोग के प्रारूप से मेल खाता था।

फर्जी QR Code का तकनीकी विश्लेषण

धोखाधड़ी को पूरी तरह प्रमाणित करने के लिए पुलिस ने कार्ड पर छपे QR Code (Quick Response Code) को स्कैन किया। असली सरकारी दस्तावेजों का क्यूआर कोड स्कैन करने पर वह सीधे सरकारी डेटाबेस या सर्वर से लकि होता है और वहां सुरक्षित डेटा दिखाता है।

लेकिन इस नकली कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करने पर पाया गया कि वह किसी भी आधिकारिक सरकारी डेटाबेस से जुड़ा हुआ नहीं था। उसमें केवल वही सीमित जानकारी टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाई दे रही थी जो डमी अकाउंट बनाते समय पुलिस अधिकारी ने खुद टाइप की थी। इससे साफ हो गया कि यह गरीब केवल एक स्क्रिप्ट के जरिए नकली पीडीएफ (PDF) फाइलें तैयार कर रहा था।

5. पहचान की चोरी से लेकर बैंक फ्रॉड तक: इन फर्जी दस्तावेजों

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के जाली दस्तावेज समाज और देश की सुरक्षा के लिए एक अत्यंत गंभीर खतरा पैदा करते हैं। मात्र 100 रुपये में मलिन वाली यह फर्जी आईडी देश के बैंकिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान

पहुंचा सकती थी।

साइबर अपराधों में होने वाला दुरुपयोग

जांच में सामने आया है कि इन नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल कई प्रकार के अवैध और राष्ट्रवरीधी कामों में धड़ल्ले से किया जा सकता था:

>> पहचान की चोरी (Identity Theft): किसी निर्दोष नागरिक के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे अपराध में फंसाना।

>> बैंकगि धोखाधड़ी (Financial Fraud): जाली आईडी के आधार पर बैंकों में डमी खाते खोलना और लोन लेकर गायब हो जाना।

>> अवैध समि कार्ड (Fake SIM Cards): बना किसी वैध वेरिफिकेशन के फर्जी नाम पर समि कार्ड एक्टिव करना, जिनका इस्तेमाल रंगदारी या साइबर ठगी में होता है।

>> सरकारी योजनाओं का गलत लाभ: बना पात्रता के फर्जी नविस या जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अवांछित लाभ उठाना, जो कि अक्सर बड़े घोटालों का रूप ले लेता है। इस विषय पर अधिक समझने के लिए आप साइबर सरकार का घोटाला: कैसे सरकारी योजनाओं के नाम पर हुआ करोड़ों का घोटाला भी पढ़ सकते हैं।

6. दमन से बदिशी साव और पटना से संतोष कुमार गरिफ्तार: ऐसे हु

डमी ऑपरेशन के जरिए पुख्ता सबूत मिलने के बाद, दिल्ली पुलिस की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने अपराधियों के डिजिटल पदचिहनों (Digital Footprints) को ट्रैक करना शुरू किया। पुलिस ने उस यूपीआई (UPI) अकाउंट और मोबाइल नंबर की डिटिल्स निकाली, जिसका उपयोग वेबसाइट पर पैसे लेने के लिए किया जा रहा था।

दमन और पटना में बैंक-टू-बैंक छापेमारी

जांच के दौरान पैसे प्राप्त करने वाला बैंक खाता बदिशी सावनाम के व्यक्तिका निकला, जो उस समय केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव (Daman and Diu) में छुपा हुआ था। दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम ने तुरंत दमन पहुंचकर बदिशी साव को धर दबोचा।

कड़ी पूछताछ के दौरान बदिशी साव ने कबूला कि वह केवल वित्तीय लेनदेन और फ्रंट-एंड संभालता था, जबकि इस पूरी वेबसाइट का मास्टरमाइंड और बैंक एंड डेवलपर बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला संतोष कुमार है। इसके बाद पुलिस ने बना वक्त गंवाए पटना में छापेमारी की और संतोष कुमार को भी उसके ठिकाने से गरिफ्तार कर लिया।

जब्त कए गए डजिटल उपकरण

आरोपियों के पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है:

- >> अपराध में इस्तेमाल होने वाले हाई-एंड लैपटॉप और स्मार्टफोन।
- >> वेबसाइट का ओरजिनल सोर्स कोड (Source Code) और होस्टिंग सर्वर के क्रेडेंशियल्स।
- >> हजारों ठगे गए ग्राहकों की सूची (list) और उनके द्वारा अपलोड किया गया व्यक्तिगत डेटा।
- >> दोनों आरोपियों के बीच हुई व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट्स के डजिटल साक्ष्य।

7. वॉलेट रचार्ज से लेकर फर्जी आईडी प्रिंट होने तक: जानिए कै

संतोष कुमार और बदिशी साव ने मलिकर इस अवैध धंधे को पूरी तरह से ऑटोमेटेड (Automated) बना रखा था ताकि उन्हें हर यूजर के लिए खुद मेहनत न करनी पड़े। उन्होंने बकायदा एक व्यवस्थित यूजर इंटरफेस तैयार किया हुआ था।

अवैध बजिनेस मॉडल के मुख्य चरण

यह अवैध वेबसाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में काम करती थी:

- >> पंजीकरण (Registration): सबसे पहले यूजर को वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और ईमेल आईडी दर्ज कर लॉगइन क्रेडेंशियल बनाने होते थे।
 - >> डजिटल वॉलेट रचार्ज (Wallet Recharge): दस्तावेज बनाने से पहले यूजर को अनविर्य रूप से दिए गए क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी पर पैसे भेजकर अपना इन-साइट वॉलेट न्यूनतम 100 रुपये से रचार्ज करना पड़ता था।
 - >> डेटा फ्लिगि (Data Input): वॉलेट में पैसे आते ही यूजर के सामने आधार, पैन, वोटर आईडी या सल्लिबस सर्टिफिकेट जैसे कई विकल्प खुल जाते थे। वहां यूजर को अपनी मर्जी का नाम, पति का नाम, जन्मतथि और फोटो अपलोड करने की पूरी छूट थी।
 - >> इंस्टेंट पीडीएफ जनरेशन (Instant PDF Generation): जैसे ही यूजर सबमिट बटन पर क्लिक करता था, बैकएंड स्क्रिप्ट स्वचालित रूप से एक नकली पीडीएफ फाइल तैयार कर देती थी जिससे यूजर आसानी से प्रिंट (Print) कर सकता था।
- यदि आप किसी प्रामाणिक परीक्षा जैसे किराष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा आधिकारिक स्रोतों से ही पाठ्यक्रम डाउनलोड करें। इसके लिए आप हमारा वसितृत गाइड UGC NET 2026: पेपर 1 और 2 का पूरा सल्लिबस और नया एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं ताकि आप किसी फर्जी लकि के झांसे में न आएं।

8. दिल्ली पुलिस की आम जनता से अपील: सरकारी दस्तावेजों के लिए

इस बड़े अंतर-राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश करने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के नागरिकों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने साफ कथित है कि शॉर्टकट के चक्कर में किसी भी अनधिकृत वेबसाइट पर अपनी नजि जानकारी साझा करना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।

सुरक्षित रहने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

>> यूआरएल (URL) की जांच करें: हमेशा ध्यान रखें कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों के अंत में .gov.in या .nic.in होता है। किसी भी .in, .com या .net वाली नजि साइट पर अपना सरकारी दस्तावेज न बनाएं।

>> स्टेटस चेक (Status Check): अपने किसी भी आवेदन की स्थिति जानने के लिए केवल राष्ट्रीय सरकारी पोर्टल (National Government Portal) पर ही स्टेटस चेक करें।

>> नजि डेटा की सुरक्षा: किसी भी अनधिकृत ऐप या पोर्टल पर अपना फगिरप्रति, आईरसि स्कैन, या आधार नंबर दर्ज न करें। ऐसा करने से आपकी पूरी जमापूंजी गायब हो सकती है।

>> साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930: यदि आपको ऐसी किसी भी संदिग्ध वेबसाइट या फ्रॉड गरीह के बारे में पता चलता है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रपिर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर शकियात दर्ज करें या टोल-फ्री नंबर 1930 पर कॉल करें।

नष्कर्ष (Conclusion): तकनीक ने जहां हमारे जीवन को आसान बनाया है, वहीं बदिशी साव और संतोष कुमार जैसे अपराधियों ने इसका दुरुपयोग कर देश की सुरक्षा प्रणालियों को चुनौती देने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस द्वारा इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश करना इस बात का प्रमाण है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। एक जम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी भी यह जम्मेदारी बनती है कि हम सतर्क रहें, किसी भी लोकलुभावन या शॉर्टकट दावों वाली फर्जी वेबसाइट bkprint.in जैसी जगहों से दूर रहें और हमेशा केवल भारत सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रों या आधिकारिक डिजिटल पोर्टल्स का ही उपयोग करें। सतर्कता ही साइबर अपराध से बचने का सबसे अचूक हथियार है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (IFSO) ने bkprint.in नाम की एक अवैध वेबसाइट का भंडाफोड़ कथित है, जो ऑनलाइन पैसे लेकर नकली सरकारी दस्तावेज जैसे आधार और पैन कार्ड तैयार कर रही थी।

इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गरिफ्तार कथित है। पहला आरोपी बदिशी साव है जिसे दमन और दीव से पकड़ा गया, और दूसरा मुख्य मास्टरमाइंड संतोष कुमार है जिसे पटना, बिहार से गरिफ्तार कथित गया है।

MSNTARGET.COM

<https://msntarget.com>

फर्जी वेबसाइट द्वारा बनाए गए कार्डों पर मौजूद QR Code किसी भी आधिकारिक सरकारी डेटाबेस से लकि नहीं होते हैं। इसे स्कैनर से चेक करने पर केवल वही जानकारी दखिती है जो यूजर ने खुद भरी होती है, कोई सरकारी सत्यापन नहीं होता।

इन जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल गंभीर अपराधों जैसे पहचान की चोरी (Identity Theft), बैंकों में फर्जी खाते खोलकर वित्तीय धोखाधड़ी करने, अवैध रूप से समि कार्ड हासलि करने और सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने में कथिा जा सकता है।

यह वेबसाइट पूरी तरह ऑटोमेटेड थी। ग्राहकों को पहले यूपीआई के जरएि अपना डिजिटल वॉलेट कम से कम 100 रुपये से रचिार्ज करना पड़ता था, जसिके बाद वे मनचाही फर्जी जानकारी और फोटो भरकर तुरंत जाली पीडीएफ (PDF) डाउनलोड कर सकते थे।

यदआपको ऐसी कसिी भी फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाने वाली वेबसाइट का पता चलता है, तो आप तुरंत भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर ऑनलाइन शकियात दर्ज कर सकते हैं या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं।